राजस्थान राज्य

बनाम

फिरोज खान उर्फ आरिफ खान

(आपराधिक अपील संख्या 750/2006)

17 मई, 2016

[अभय मनोहर सप्रे और अशोक भूषण, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता,1973: s.378 (3)-यू/एस.378 (3) द्वारा की गई अपील के लिए अनुमति देने के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में रखे अनुमति वाले मापदंड। - चर्चा की गई-तत्काल मामले में प्रतिवादी पर 11 साल की लड़की की हत्या के अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था-निचली अदालत ने प्रतिवादी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया-राज्य का आवेदन यू/एस।378(3) बिना कारण बताए उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकृत अनुमति के लिए-आयोजितःयह स्पष्ट रूप से दिमाग का उपयोग न करने का मामला था-मामले को पुनर्विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया गया-दंड संहिता, 1860 -s.302।

अपील की अनुमति देते हुए और मामले को उच्च न्यायालय को प्रेषित करते हुए, अदालत ने कहाःयह न्यायाधीशों द्वारा मामले में पूरी तरह से विचार न करने का एक स्पष्ट मामला था क्योंकि आदेश में न तो तथ्यों को निर्धारित किया गया है और न ही पक्षों की दलीलें और न ही निष्कर्ष और न ही कारण बताए अनुमति हैं कि अपील दायर करने की अनुमति क्यों अपीलकर्ता को अस्वीकार कर दी गई है।आवेदन पर निर्णय लेने में उच्च न्यायालय का आकस्मिक दृष्टिकोण कानून के खिलाफ है। कानून के अनुसार गुण -दोष के आधार पर नए सिरे से अपील करने की अनुमति देने

के लिए अपीलकर्ता द्वारा किए अनुमति आवेदन पर निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेज दिया जाता है।[पारस 13 और 14] [698-ए, सी]

महाराष्ट्र राज्य बनाम सुजय मंगेशकर 2008 (13) एससीआर 750:(2008) 9 एस. सी. सी. 475-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

2008 (13) एस. सी. आर. 750 संदर्भित पारस 9,13

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : दाण्डिक अपीलीय संख्या.750/2006

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की न्यायिक व्यवस्था से अपील करने के लिए आपराधिक अनुमति क्रमांक 227/2005 में पारित निर्णय और आदेश 28.10.2005 से ।

पुनीत परिहार, मिलिंद कुमार, अधिवक्ता।अपीलकर्ता के लिए।

न्यायालय का निर्णय, न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे, द्वारा पारित किया गया:-

1. यह अपील राजस्थान राज्य द्वारा जोधपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.2005 को पारित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें 2005 की अपील संख्या 227 की आपराधिक अनुमति दी गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने यहां अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया था। 2002 के सत्र परीक्षण मामले संख्या 48 में सत्र न्यायाधीश, जैसलमेर द्वारा पारित दिनांक 13.08.2004 के फैसले के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) की धारा 378 (3) के तहत अपील दायर करने की अनुमति मांगी गई है।

2. अपील में शामिल संक्षिप्त बिंदु को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता की शिकायत को समझने के लिए कुछ तथ्यों को छोड़कर तथ्यों को विस्तार से बताना आवश्यक नहीं है।

3. जिला और सत्र न्यायाधीश, जैसलमेर की अदालत में 2002 के सत्र परीक्षण मामले संख्या 48 में पुलिस स्टेशन रामगढ़, जिला जैसलमेर में प्राथमिकी संख्या 44/2002 दर्ज क्रमांक के अनुसार प्रतिवादी (आरोपी) पर भारतीय दंड संहिता 1860 (इसके बाद "आई. पी. सी". के रूप में संदर्भित) की धारा 302 के तहत लगभग 11 वर्ष की आयु के एक लिली खान की हत्या के अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चलाया गया।अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य पेश किए।

4. सत्र निर्णय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना करने पर प्रतिवादी को संदेह का लाभ देकर हत्या के आरोप से बरी कर दिया।

5. राजस्थान राज्य ने प्रत्यर्थी के दोषमुक्ति से व्यथित होकर संहिता की धारा 378 (3) के तहत उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन दायर किया।

6. आक्षेपित आदेश से, उच्च न्यायालय ने अनुमति देने से इनकार कर दिया और तदनुसार राज्य द्वारा किए अनुमति आवेदन को खारिज कर दिया; यह इस आदेश के खिलाफ है, राज्य ने विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से यह अपील दायर की है।

7. प्रतिवादी को अपील की याचिका दायर करने की सूचना दी गई थी, लेकिन नोटिस देने के बावजूद, प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ है।

8. राजस्थान राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

9. अपीलार्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने केवल एक प्रस्तुति दी है।उनके अनुसार, उच्च न्यायालय ने अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन को खारिज

करते हुए कोई कारण नहीं बताया और इसलिए विवादित आदेश को कानून की दृष्टि में गलत माना जाता है।यह उनका निवेदन था कि सत्र न्यायाधीश के निर्णय में कई विसंगतियां और त्रुटियां थीं जिनके खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगी गई थी और इसलिए, यह एक उपयुक्त मामला था जहां उच्च अपील न्यायालय को मामले की आगे की जांच के लिए अपील करने की अनुमति देनी चाहिए थी।अपने निवेदन के समर्थन में उन्होंने महाराष्ट्र राज्य बनाम सुजय मंगेशकर (2008) 9 एस. सी. सी. 475 में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया।

10. हम अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आग्रह किए गए निवेदन के साथ आंशिक रूप में सहमत होने के लिए इच्छुक हैं।

11. यह प्रश्न कि संहिता की धारा 378 (3) के तहत की गई अपील के लिए अनुमति देने के आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा कैसे निराकृत जाना चाहिए और उच्च न्यायालय को किन मापदंडों को ध्यान में रखना चाहिए, अब एकीकृत नहीं है। इस मुद्दे की जाँच इस अदालत द्वारा महाराष्ट्र राज्य बनाम सुजय मंगेशकर (ऊपर) न्यायमूर्ति C.K.Thakker में की गई थी, जो पैरा 19,20,21 और 24 में आयोजित पीठ की ओर से निम्नानुसार बोल रहे थेः

> "19.अब, संहिता की धारा 378 में दोषमुक्ति के मामले में राज्य द्वारा अपील दायर करने का प्रावधान है।उप-धारा (3) घोषणा करती है कि उच्च न्यायालय की अनुमति के अलावा किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।इसलिए, यह उस राज्य के लिए आवश्यक है जहां वह सत्र अदालत द्वारा दर्ज किए अनुमति दोषमुक्ति के आदेश से व्यथित है, वह संहिता की धारा 378 की उप-धारा (3) द्वारा आवश्यक अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन दायर करे।

20. हालाँकि, हमारी राय में इस प्रश्न पर निर्णय लेने में कि क्या आवश्यक अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, उच्च न्यायालय को अपने दिमाग को लागू करना चाहिए, इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या प्रथमदृष्टया मामला बनाया गया है या बहस योग्य बिंदु उठाए अनुमति हैं और न कि क्या दोषमुक्ति के आदेश को दरकिनार कर दिया जाएगा या नहीं।

21. यह सार्वभौमिक अनुप्रयोग के कानून के एक संक्षिप्त सार प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि निचली निचली अदालत द्वारा दर्ज किए अनुमति दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ अपील गुणागुण ने की अनुमति मांगने वाली प्रत्येक याचिका को अपील न्यायालय द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए और प्रत्येक अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए और गुण-दोष के आधार पर निराकृत जाना चाहिए।लेकिन यह भी नहीं देखा जा सकता है कि उस स्तर पर, निचली अदालत अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के संक्षिप्त विवरण में प्रवेश नहीं करेगी और यह देखते हुए अनुमति देने से इनकार कर देगी कि निचली निचली अदालत द्वारा दर्ज किए अनुमति दोषमुक्ति के निर्णय को "विकृत" नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, कोई अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

24. हम जल्दबाजी में यह स्पष्ट कर सकते हैं कि यह नहीं समझा जा सकता है कि हमने एक अलंघनीय नियम निर्धारित किया है कि निचली निचली अदालत द्वारा दर्ज किए अनुमति दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ अपील न्यायालय द्वारा किसी भी अनुमति से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।हम केवल यह कहते हैं कि ऐसे

मामलों में अपील न्यायालय को प्रासंगिक सामग्री पर विचार करना चाहिए, अभियोजन पक्ष के गवाहों की शपथ गवाही रिकॉर्ड करना चाहिए कि राज्य द्वारा मांगी गई अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए और निचली निचली अदालत द्वारा दर्ज किए अनुमति दोषमुक्ति के आदेश को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।जहाँ अपील न्यायालय द्वारा विचार का अनुप्रयोग किया जाता है और ऐसे दृष्टिकोण के समर्थन में कारण (संक्षिप्त में हो सकते हैं) दर्ज किए जाते हैं, वहाँ न्यायालय के आदेश को अवैध या आपत्तिजनक नहीं कहा जा सकता है।हालाँकि, साथ ही, यदि तर्क योग्य बिंदु उठाए अनुमति हैं, यदि अभिलेख पर सामग्री गहरी जांच और साक्ष्य की पुनः पुनर्विलोकन , पुनर्विलोकन या पुनर्विचार का खुलासा गुणागुण ती है, तो अपील न्यायालय को मांगी गई अनुमति देनी चाहिए और योग्यता के आधार पर अपील पर निर्णय लेना चाहिए।हाथ में मामले में, उच्च न्यायालय ने, सम्मान के साथ, न तो किया।उच्च न्यायालय की राय में, मामले में अनुमति की मंजूरी की पुनः आवश्यकता नहीं थी।लेकिन यह इस तरह की अनुमति से इनकार करने के कारणों को दर्ज करने में भी विफल रहा। "

12. अब इस मामले के तथ्यों में आते हुए, आक्षेपित आदेश को शाब्दिक रूप से पुनः प्रस्तुत करना उचित है।

"Heard-._

अनुमति का कोई मामला नहीं बनता है।तदनुसार,, अपील करने की अनुमति खारिज कर दी अनुमति।"

13. हम यह देखने के लिए विवश हैं कि उच्च न्यायालय ने बिना कोई कारण बताए विवादित आदेश पारित करने में घोर गलती की है।हमारी सुविचारित राय में, यह विद्वान न्यायाधीशों द्वारा मामले में पूरी तरह से ध्यान न देने का एक स्पष्ट मामला था क्योंकि आक्षेपित आदेश या तो तथ्यों को निर्धारित करता है और न ही पक्षों की प्रस्तुतियों को और न ही निष्कर्षों को और न ही कारणों को कि अपील दायर करने की अनुमति क्यों अपीलकर्ता को अस्वीकार कर दी गई है।इसलिए, हम आवेदन पर निर्णय लेने में उच्च न्यायालय के आकस्मिक दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं, जो हमारे विचार में महाराष्ट्र राज्य बनाम सुजय मंगेशकर (उपरोक्त) के मामले में इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून के खिलाफ है।

14. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए।इस प्रकार अपील सफल होती है और तदनुसार अनुमति दी जाती है और विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।महाराष्ट्र राज्य बनाम सुजय मंगेशकर (उपरोक्त) में इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार गुण -दोष के आधार पर नए सिरे से अपील करने की अनुमति देने के लिए अपीलकर्ता द्वारा किए अनुमति आवेदन पर निर्णय लेने के लिए मामला उच्च न्यायालय को भेज दिया गया है।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने मामले के गुण -दोष पर अपना दिमाग नहीं लगाया है और यह देखते हुए मामले को रिमांड पर ले लिया है कि यह एक अनुचित आदेश था।उच्च न्यायालय तदनुसार इस आदेश में की गई हमारी किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना गुण-दोष के आधार पर आवेदन पर निर्णय करेगा।

16. चूंकि मामला पुराना है, इसलिए हम उच्च न्यायालय से इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर मामले पर फैसला करने का अनुरोध करते

हैं।चूंकि प्रतिवादी को नोटिस दिए जाने के बावजूद कोई भी इस अदालत में उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उच्च न्यायालय प्रतिवादी को अनुमति देने के लिए आवेदन का एक नया नोटिस जारी करेगा और फिर निर्देश के अनुसार आवेदन पर निर्णय लेगा।

देविका गुजराल अपील को मंजूरी दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही पामाणिक माना होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।